नईदुनिया

बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रबंधन शिक्षा को अपना दायरा बढ़ाना होगा : सीईए

नई दिल्ली

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने प्रबंधन शिक्षा के लिए एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। नोएडा में 16वें इंडियन मैनेजमेंट कान्क्लेव में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले व्यवधानों के कारण दुनिया तेजी से बदल रही है।

पारंपरिक कुशलता के बजाय लचीलेपन, गहन सोच और चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह

ऐसे में प्रबंधन संस्थानों को पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर छात्रों को इन नई वास्तविकताओं के लिए तैयार करना होगा। उन्हें केवल एआई केंद्रित विषयों को जोड़ने के बजाय अपने पाठ्यक्रम में समझदारी, मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता, गहरी सोच और चरित्र को केंद्र में रखना चाहिए। नागेश्वरन ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक रूप से प्रबंधन का जोर लीन आपरेशन, जस्ट-इन-टाइम सिस्टम और एकल-स्रोत आपूर्ति श्रृंखला जैसी कुशलता पर था, लेकिन वैश्विक झटकों के कारण अब ये माडल कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती होड़ और आपूर्ति व्यवस्थाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कारण प्रबंधकों को अब अतिरिक्त क्षमता बनाने, विकल्पों को बनाए रखने और संगठनों में मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, भले ही इससे लागत बढ़ जाए।

नागेश्वरन के अनुसार, बिना किसी रुकावट वाली कुशलता और एकल-स्रोत वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। यह कम से कम एक पीढ़ी तक वापस नहीं आएगी। उन्होंने जोर दिया कि जिन प्रबंधकों को केवल संतुलन साधने और लागत कम रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उन्हें अब एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया का सामना करना पड़ रहा है।

नागेश्वरन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में भू-राजनीतिक तनावों जैसे होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधानों ने भारतीय व्यवसायों को आपूर्ति स्रोतों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। सीईए ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों से आग्रह किया कि वे पश्चिमी माडलों की नकल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ढांचे विकसित करें।

न्यूज ब्रीफ

टाटा और नेक्सपेरिया ने की साझेदारी, भारत में बनेंगी पावर कंट्रोल चिप्स

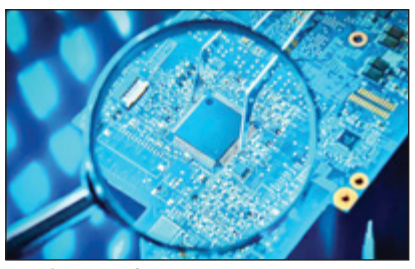

एम्स्टर्डम। डच सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माता नेक्सपेरिया ने भारतीय दिग्गज टाटा इलेक्ट्रानिक्स के साथ भारत में कंप्यूटर चिप्स के निर्माण और पैकेजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। यह कदम चीनी मूल कंपनी विंगटेक से नेक्सपेरिया के अलगाव को और मजबूत करेगा, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। नेक्सपेरिया और टाटा इलेक्ट्रानिक्स मिलकर नेक्सपेरिया के पावर कंट्रोल चिप्स का उत्पादन करेंगे। ये चिप्स गुजरात के धोलेरा में टाटा के 11 अरब डालर के निर्माणाधीन संयंत्र में बनाए जाएंगे। कंपनियां असम के जागीरोड में टाटा की पैकेजिंग सुविधा में चिप्स की परीक्षण (टेस्टिंग) और असेंबलिंग (जोड़ना) में भी सहयोग करेंगी। हालांकि, वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है, दोनों भविष्य की तकनीक विकसित करने में भी मिलकर काम करेंगे। टाटा इलेक्ट्रानिक्स के एक अधिकारी ने इस व्यापक साझेदारी को भारत में एक विश्व-स्तरीय, एकीकृत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नेक्सपेरिया साधारण चिप्स का एक प्रमुख निर्माता है। यह साझेदारी विंगटेक से नेक्सपेरिया के अलगाव को मजबूत करती है, जो डच सरकार के हस्तक्षेप से शुरू हुआ था।

आईसीआईसीआई बैंक ने वेबसाइट और नेट बैंकिंग के यूआरएल बदले

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बैंक ने अपनी वेबसाइट और नेट बैंकिंग के वेब पते (यूआरएल) में बदलाव किया है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत उठाया गया है, जिसके तहत बैंक को अपने पुराने डोमेन को नए डाट बैंक डाट इन डोमेन पर स्थानांतरित करना पड़ा है। बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजी गई सूचना अनुसार, नेट बैंकिंग का पुराना पता रिटेल बैंकिंग डाट आईसीआईसीआई बैंक डाटकाम अब बदलकर रिटेल बैंकिंग डाट आईसीआईसीआई बैंक डाट इन कर दिया गया है। इसी तरह, बैंक की मुख्य वेबसाइट आईसीआईसीआई डाट बैंक डाट इन डोमेन पर उपलब्ध होगी। यह बदलाव ग्राहकों के मौजूदा ग्राहक आईडी, पासवर्ड या बैंक खाते की जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ग्राहक अपने पुराने लागिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ही नए नेट बैंकिंग पोर्टल पर आसानी से लाग इन कर सकेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नए पंजीकरण या नया लागिन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 19 सितंबर, 2026 को आईमोबाइल ऐप की सेवाएं कुछ घंटों के लिए निर्धारित रखरखाव के कारण बंद रहेंगी। यह एक पूर्व-निर्धारित कार्य है और ग्राहकों को इससे अवगत कराया गया है।

कृषि में नवाचार से उपभोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिएः एफएसएसएआई

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक प्रमुख अधिकारी ने कृषि क्षेत्र में नवाचार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खेती में नवाचार का मकसद केवल फसल की पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। उन्होंने भारतीय कृषि-रसायन महासंघ की 9वीं सालाना आम बैठक में कहा कि नवाचार और विनियमन को प्रतिद्वंद्वी के बजाय सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवाचार को किसी खाद्य उत्पाद की सुरक्षा को कम करने के तरीके के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए; इसके बजाय, इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए सुरक्षा का स्तर बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के अवशेषों की सीमा वैज्ञानिक सबूतों, जोखिम-आधारित तरीकों और निगरानी पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों को कम करने के बजाय, फसलों के इस्तेमाल के बाद नए या उभरते हुए दूषित पदार्थों का पता लगाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

चंडीगढ़ में सीएनजी-पीएनजी हुई सस्ती, त्योहारी सीजन से पहले प्रशासन का बड़ा तोहफा

प्राकृतिक गैस पर वैट 12.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया

चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में त्योहारी सीजन से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने कार्म्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) को 12.5 फीसदी से घटाकर सीधे 5 फीसदी कर दिया है। वैट की दर में 7 फीसदी से अधिक की इस ऐतिहासिक कटौती से शहर में लाखों उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। ये नई दरें हाल ही में लागू हो गई हैं, जिससे ईंधन की कीमतें तुरंत प्रभावी हुई हैं। इस महत्वपूर्ण कटौती के परिणामस्वरूप, घरेलू पीएनजी की कीमतों में लगभग 3.42 रुपये प्रति एससीएम तक की कमी आने का अनुमान है। फिलहाल चंडीगढ़ में घरेलू पीएनजी की कीमत लगभग 54.70 रुपये प्रति एससीएम है। इसी तरह, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गैस की खुदरा कीमतों पर भी इसका असर दिखेगा, जिससे वाहन चालकों और आटो-कैब आपरेटरों को सीधा फायदा होगा। चंडीगढ़ प्रशासन का यह कदम दोहरे उद्देश्य से प्रेरित है। पहला शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करना और इसके लिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन जैसे सीएनजी और पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए शहर में नैचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आसान होगा।

प्रशासन ने शहर के लगभग 1.70 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सस्ती गैस होने से लोग पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों को छोड़कर पीएनजी की ओर तेजी से आकर्षित होंगे। गौरतलब है कि वैट एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु के उत्पादन से लेकर ग्राहक तक पहुंचने के हर चरण पर लगाया जाता है। हालांकि भारत में 1 जुलाई 2017 से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू हो गया है, भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस (जैसे सीएनजी और पीएनजी) को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

यूपीआई एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं, सरकार बनाएगी निगरानी तंत्र, एमडीआर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर भी लगाएगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने 15 अक्टूबर से कुछ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है, जिससे व्यापारियों द्वारा संभावित मूल्य वृद्धि की आशंकाओं को दूर किया जा सके। 15 अक्टूबर से कुछ खास व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर लगेगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये होगा। हालांकि, छोटे व्यापारियों (जिनका मासिक यूपीआई लेनदेन 1,00,000 रुपये तक है), 2,000 रुपये तक के पर्सन-टु-मर्चेंट लेनदेन और परिवार व दोस्तों के बीच के पीयर-टु-पीयर लेनदेन को इस शुल्क से पूरी तरह छूट मिलेगी। एमडीआर लागू होने के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि व्यापारी इन शुल्कों की भरपाई के लिए कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस बात की निगरानी की जाएगी कि व्यापारी एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर न डालें। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह तंत्र किस प्रकार का होगा, क्योंकि अनुचित मुनाफाखोरी को रोकने के लिए फिलहाल कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। सरकार एमडीआर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लगाएगी, लेकिन पंजीकृत कारोबारी चुकाए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकेंगे।

बोर्डरूम विवाद से टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 39,000 करोड़ घटा

मुंबई

टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में खासी गिरावट दर्ज की गई, जिससे समूह का बाजार पूंजीकरण करीब 39,000 करोड़ रुपये घट गया। यह गिरावट समूह के शीर्ष नेतृत्व में चल रही खींचतान का सीधा परिणाम है, जहां टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने के बोर्ड प्रस्ताव को अवैध करार दिया है। इस शीर्ष-स्तरीय खींचतान ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

टाटा संस की बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस पुनर्नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध करार दिया। शीर्ष नेतृत्व में इस खींचतान का असर समूह के शेयरों पर साफ दिखा।

जहां निफ्टी 50 में 0.33 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं निफ्टी टाटा 25 कैप सूचकांक 1.12 फीसदी नीचे बंद हुआ। समूह की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 3.9 फीसदी गिरकर 2,105 रुपये पर बंद हुआ, जिससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में अकेले 30,754 करोड़ रुपये की कमी आई। टाटा केमिकल्स को भी भारी नुकसान हुआ और यह 11 फीसदी गिरकर 603.25 रुपये पर बंद हुआ।

समूह की अन्य कंपनियों में टाटा टेक्नोलाजीज 4.8 फीसदी और टाटा एलेक्सी 3.4 फीसदी नीचे बंद हुए। क्यूईडी कैपिटल एडवाइजर्स में एक मैनेजिंग पार्टनर ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम तौर पर शीर्ष नेतृत्व के बीच टकराव से बाजार में हलचल मच जाती है, लेकिन टाटा समूह एक ऐसा संस्थान है जो मजबूत बुनियाद पर टिका है, न कि किसी एक व्यक्तित्व पर। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कारोबारी संचालन और आईपीओ को लेकर चल रहा यह बोर्डरूम टकराव कुछ समय के लिए अस्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन समूह की नींव इतनी मजबूत है कि वह इस मुश्किल दौर से निकल सकता है और लंबे समय में शेयरधारकों के मूल्यों को सुरक्षित रख सकता है।

यह गिरावट निफ्टी आईटी सूचकांक में देखी गई व्यापक कमजोरी के अनुरूप भी थी, जो दिन के अंत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला प्रमुख सूचकांक रहा।

किआ ने लान्च की 460 किमी रेंज वाली पीवी7 इलेक्ट्रिक वैन

नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी किआ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन श्रृंखला में नई पीवी7 इलेक्ट्रिक वैन पेश की है। पैसेंजर संस्करण में बाजार के अनुसार, इस वैन में 11 लोगों तक बैठने की सुविधा होगी, जबकि कार्गो संस्करण 1,200 किलोग्राम तक भार उठा सकेगा। इसे यात्रियों और सामान ढोने, दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। कंपनी इसे 2027 की दूसरी छमाही में दक्षिण कोरिया और यूरोप के बाजारों में उतारने की योजना बना रही है। भारत में इसके लान्च की अभी घोषणा नहीं हुई है। पीवी7 को किआ के ई-जीएमपी.एस इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है। इसमें 71.5 और 96.2 किलोवाट-घंटे की बैटरी के विकल्प मिलेंगे। आगे लगी इलेक्ट्रिक मोटर 200 किलोवाट यानी करीब 268 हार्सपावर की ताकत और 420 न्यूटन मीटर टार्क देती है। लान्ग रेंज कार्गो माडल एक बार चार्ज करने पर 460 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकेगा।

कर्नाटक में दूध 8 रुपए महंगा करने की मांग, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम

डेयरी किसानों का आरोप, उत्पादन लागत बढ़ने और हरे चारे की कमी से गहराया संकट

बैंगलूर

कर्नाटक के उपभोक्ताओं को जल्द ही दूध के बढ़े हुए दाम का झटका लग सकता है। राज्य के दुग्ध उत्पादक संघों ने दूध की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि की मांग की है, और इस संबंध में सरकार को तीन दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह मांग बेंगलुरु प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस में उठाई गई। दुग्ध उत्पादक संघों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और दूध के घटते उत्पादन ने उन पर भारी दबाव डाला है।

बामुल, चामुल और मांड्या मिल्क जैसे बड़े मिल्क यूनियन इस मांग के पक्ष में हैं। उन्होंने सरकार से दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन (इंसेंटिव) में भी बढ़ोतरी की मांग की है। बामुल मिल्क यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया कि डेयरी एसोसिएशन पिछले आठ महीनों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डेयरी किसान इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। कम बारिश के कारण हरे चारे की कमी है, वहीं पशु आहार और कच्चे माल की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने से दूध उत्पादन की कुल लागत काफी बढ़ गई है, जिससे किसानों के लिए मवेशी पालना मुश्किल हो रहा है। संघों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला नहीं लिया गया, तो वे विधान सौध तक विरोध मार्च निकालेंगे। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले नंदिनी जैसे ब्रांड का दूध बेहद महंगा हो जाएगा। इससे न केवल रसोई का बजट गड़बड़ाएगा, बल्कि मिठाई और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं।

टाटा संस में चंद्रशेखरन का कार्यकाल विस्तार, नोएल टाटा की आपत्ति

नई दिल्ली

मुंबई में हुई टाटा समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर अगले पांच साल तक वे समूह का नेतृत्व करते रहेंगे। हालांकि, इस फैसले पर टाटा परिवार के सदस्य नोएल टाटा ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अन्य बोर्ड सदस्यों के पूर्ण समर्थन के बाद चंद्रशेखरन को दोबारा कमान सौंप दी गई। इस घटना ने दोनों अहम शख्सियतों की भूमिकाओं और उनके पारिश्रमिक में बड़े अंतर को भी उजागर किया है।

चेयरमैन की तीसरी नियुक्ति पर बोर्ड मेंबर्स का समर्थन, पर नोएल टाटा नहीं थे सहमत

टाटा समूह के भीतर यह चर्चा तेज है कि एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार से नोएल टाटा नाखुश हैं। बोर्ड में वोटिंग के दौरान नोएल टाटा ने अपनी असहमति स्पष्ट की। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई और टाटा परिवार के अहम सदस्य हैं। वे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन सहित समूह की कई कंपनियों में गैर-कार्यकारी भूमिकाओं में हैं। दूसरी ओर, एन चंद्रशेखरन पिछले 10 साल से टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और अब अगले 5 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोनों के बीच मतभेद का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन उनकी भूमिकाओं और पारिश्रमिक में बड़ा अंतर है। आंकड़ों के अनुसार, नोएल टाटा को विभिन्न गैर-कार्यकारी बोर्ड भूमिकाओं के लिए सालाना करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। इसमें बोर्ड मीटिंग फीस और डायरेक्टर कमीशन शामिल हैं। वहीं, एन चंद्रशेखरन का सालाना पैकेज 135 से 155 करोड़ रुपये के बीच बताया जाता है, जिसमें बुनियादी वेतन के साथ कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा कमीशन भी शामिल है। इस तरह, चंद्रशेखरन का पैकेज नोएल टाटा को मिलने वाले पारिश्रमिक से लगभग 27-30 गुना अधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से उनकी भूमिकाओं में है: चंद्रशेखरन एक कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर रोजाना के कारोबारी फैसले और रणनीति संभालते हैं, जबकि नोएल टाटा की भूमिका गैर-कार्यकारी सलाह और निगरानी तक सीमित है। जहां नोएल टाटा की संपत्ति कई स्रोतों के अनुसार 1,245 करोड़ से 12,600 करोड़ रुपये तक अनुमानित है (जो परिवार की होल्डिंग्स पर निर्भर करता है), वहीं चंद्रशेखरन का पैकेज उनकी कार्यकारी जिम्मेदारियों का सीधा परिणाम है।